वन ट्रिलियन डालर अर्थव्यवस्था को चाहिए 28 प्रतिशत की तेज विकास दर

- प्राइमरी सेक्टर को 18, सेकेंडरी को 33 और टर्सरी सेक्टर को 29 प्रतिशत की सीएजीआर दर से बढ़ना होगा आगे
- लक्ष्य को हासिल करने के लिए 105-120 लाख करोड़ के अतिरिक्त निवेश की भी जरूरत

राज्य ब्यूरो, जागरण● लखनऊ : उत्तर प्रदेश को वन ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था बनाने के सपने को अगर हकीकत में तब्दील करना है तो आर्थिक मोर्चे पर तेज विकास दर हासिल करनी होगी। प्रदेश की आर्थिक विकास दर यदि 28 प्रतिशत की दर से आगे बढ़ी तो वर्ष 2028 तक यह लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। सलाहकार एजेंसी डेलाइट इंडिया ने हाल ही में प्रदेश सरकार के साथ वन ट्रिलियन डालर अर्थव्यवस्था को लेकर साझा की गई अपनी रिपोर्ट में कुछ ऐसा ही पूर्वानुमान जताया है। यानी, वित्तीय वर्ष 2022-23 में यूपी की जीएसडीपी (सकल राज्य घरेलू उत्पाद) 22.6 लाख करोड़ रुपये के करीब थी, यदि 28 प्रतिशत सीएजीआर (चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि) से प्रदेश आगे बढ़ा तो वर्ष 2028 तक यह 78.8 लाख करोड़ तक पहुंच सकती है, जो कि वन ट्रिलियन डालर के करीब का आंकड़ा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए 105-120 लाख करोड़ रुपये के निवेश की बात भी कही गई है। हालांकि, यह लक्ष्य खासा मुश्किल दिखाई देता है, क्योंकि प्रदेश की मौजूदा विकास दर आठ से नौ प्रतिशत के दायरे में सिमटी है।

क्षेत्रवार आकलित रिपोर्ट का अनुमान कहता है कि प्राइमरी सेक्टर जिसमें कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन, खनन जैसी गतिविधियां शामिल हैं, उनको 18 प्रतिशत सीएजीआर की तेज गति से आगे बढ़ना होगा। वहीं, सेकेंडरी सेक्टर जिसमें सभी औद्योगिक गतिविधियां शामिल होती हैं, उसको 32 प्रतिशत और टर्सरी सेक्टर जिसे सेवा क्षेत्र (सर्विस सेक्टर) भी कहते हैं में 29 प्रतिशत सीएजीआर ग्रोथ वन ट्रिलियन डालर लक्ष्य में मददगार साबित हो सकती है। एजेंसी ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर विशेष जोर देते हुए इसे 33 प्रतिशत सीएजीआर की दर से आगे बढ़ाने की वकालत की है। इनमें लार्ज इंडस्ट्री के लिए 40 प्रतिशत और एमएसएमई के लिए 26 प्रतिशत का सीएजीआर हासिल करना होगा। यदि यह संभव हुआ तो जीएसडीपी में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 5.6 लाख करोड़ से बढ़कर 12.7 लाख करोड़ रुपये, द्वितीयक क्षेत्र का योगदान 5.5 लाख करोड़ से बढ़कर 22.1 लाख करोड़ और तृतीयक क्षेत्र का योगदान मौजूदा 9.6 लाख करोड़ से बढ़कर 34.5 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है। जीएसडीपी में निर्माण क्षेत्र के योगदान को भी 2.4 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 8.7 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। वरिष्ठ अर्थशास्त्री एपी तिवारी कहते हैं कि 28 प्रतिशत की तेज विकास दर प्राप्त करना किसी भी राज्य के लिए चुनौतीपूर्ण है। वर्ष 2028 तक इस लक्ष्य की प्राप्ति में दिक्कतें तो आ सकती हैं।